



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]  
N. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 9, 1985/पौष 19, 1906  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 9, 1985/PAUSA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

## वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 79-आईटीसी(पीएन)/84-85

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 1985

विषय: दिल्ली विश्वविद्यालय को 1984-85 के लिए 500 मिलियन  
येन का 'जापान' अनुदान सहायता के अर्धन भारत में उपस्कर  
लगाने/पत्तनों के लिए उपस्कर के परिवहन के लिए अपेक्षित शैक्षिक  
और अनुसंधान उपस्करों और सेवाओं का खर्च के लिए लाइसेंस  
का शर्त।

मिसिल सं. आईएस/23(8)/84:—दिल्ली विश्वविद्यालय को  
1984-85 के लिए 500 मिलियन येन का जापानी अनुदान सहायता के  
अर्धन आयातों को नियंत्रित करने का शर्त एवं निबन्धन जो इस सार्व-  
जनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित  
का जात है।

प्रकाश कृष्ण जैन,  
मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 79-आईटीसी(पीएन)/  
1984-85 दिनांक 9-1-1985 के लिए परिशिष्ट।

1984-85 के लिए 500 मिलियन (500,000,000 येन का)  
जापानी अनुदान सहायता के अर्धन भारत में उपस्कर लगाने/पत्तनों पर  
उपस्कर के परिवहन के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अनुसंधान उपस्करों  
और सेवाओं का खर्च के लिए लाइसेंस का शर्त।

खण्ड-1 सामान्य शर्तें: 1 (1)—1984-85 के लिए 500 मिलि-  
यन येन (लागत और भाड़ा) का जापानी अनुदान सहायता का उद्देश्य  
उपस्कर लगाने/पत्तनों के लिए भारत में उपस्कर के परिवहन के लिए  
अपेक्षित शैक्षिक और अनुसंधान उपस्करों और सेवाओं का खर्च के लिए  
और जापानी संभरकों को भुगतान करने और बिल विश्वविद्यालय द्वारा  
उपयोग करने से है।

1(2) आयातक के नाम में आयात लाइसेंस कुल मिलाकर 550  
मिलियन येन (लागत व भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं  
किए जाने चाहिए और उन पर एक शर्तक "1984-85 के लिए 500  
मिलियन येन जापानी अनुदान सहायता" होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय  
प्रत्यय के लिए लाइसेंस संकेत "एस/जे एन" होगा।

1(3) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को बैंक खर्च, जिसका प्रेषण सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा यदि कोई हो, के किस्मों में प्रेषण का अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारत के अधिकारों के कमेशन के प्रति यदि कोई हो तो कोई भी भुगतान अधिकारों को भारत के रूप में चुकाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के हरे भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर हरे प्रभावित किए जाएंगे।

1(4) इस अनुदान सहायता के अधिन उपकरण तथा सेवाएं केवल जापान/भारत से प्राप्त किये जाने चाहिए। क्रय आदेश केवल जापान के संभरकों के लिए ही किए जाने चाहिए।

1(5) आयात लाइसेंस 31-3-1985 तक के अवधि के साथ लागत बसा भाड़ा के आधार पर जारी किया जाएगा।

1(6) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापान के संभरकों द्वारा पानलवान वस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान का व्यवस्था होनी चाहिए। उभरे सुपुर्देग का अवधि के लिए भा इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए।

“सुपुर्देग 15-3-1985 तक पूर्ण का जाना है”

1(7) संविदा का मूल्य (केवल लागत तथा भाड़ा/जहाज पर निशुल्क मूल्य के आधार पर) येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन के भिन को हटाया जाना चाहिए) और यदि कोई हो तो भारत के अधिकारों का कमेशन शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारत के रुपये या अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भा परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यंत निशुल्क लागत-बसा भाड़ा और भाड़ा धन राशि अलग-अलग प्रदर्शित क जा सकत है, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि भाड़े का खर्च वास्तविक आधार पर देय होगा या ठेके में निविष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अनिर्दिष्ट देय धनराशि होगा।

1(8) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापान के राष्ट्रको अथवा राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित जापानी व्यापिक व्यक्तियों के साथ का जाना चाहिए।

**खण्ड-2 संभरण ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट होनी चाहिए**

2(1) 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन का अनुदान सहायता से संबद्ध इस संविदा का व्यवस्था 12 अक्टूबर, 1984 को भारत और जापान का सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार क गई है और यह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधिन होगा।

2(2) विदेशी संभरकों को भुगतान उस “भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र” (ए/प) के माध्यम से किया जाएगा जो 1984-85 के लिए जापान अनुदान सहायता के अधिन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम से सहायता एवं लेखा परक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, यू. मा. ओ. बैंक बिल्डिंग, पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

2(3) जापाना संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

2(4) जापाना संभरक भारत के दूतावास, टोकियो के परामर्श से पातलवान क व्यवस्था करने की तैयार है और उनके लिए संबंधित मात का सुपुर्देग के कार्यक्रम क भारत के दूतावास, टोकियो को सूचना देगा और अपेक्षित पात परिवहन के लिए छः सप्ताह पहले है। भारत के दूतावास, टोकियो को अधिसूचित करवाएगा जिससे उचित व्यवस्था क जाए। विशेष मामलों में, जहां भारत के आयातक यह चाहता हो, अधिसूचना का अवधि कम क जा सकता है। आवश्यक होने देते हुए प्रत्येक पानलवान

के बाद जापान संभरक को आयातक को केवल सूचना लेखने के लिए भी सहमत होना चाहिए और उसके एक प्रति भारत के दूतावास, टोकियो को भेजा जाना चाहिए।

**खण्ड-3 भारत सरकार और जापान सरकारों के बीच अनुमोदन**

3(1) जैसे ही आदेशों को अंतिम रूप दे दिए जाने हैं, लाइसेंस-धार को दोनों पाटियों द्वारा विधिबद्ध हस्ताक्षरित ठेके के चार प्रतियां या जापाना संभरकों को भारत के आयातक द्वारा दिए गए क्रय आदेश के साथ जापाना संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश के चार प्रतियां या सभा प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र में “ए/प: जारी करने के आवेदन” के दो प्रतियों सहित अथवा सचिव (टस) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, को भेजनी चाहिए। उपयुक्त प्रक्रिया संविदा के विषय वस्तु या उसका कमत के आवश्यक जाणोघनों से उत्पन्न सभा संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2) वित्त मंत्रालय (ट ईए) जापान अनुभाग 1984-85 के लिए 500 मिलियन येन का जापाना अनुदान सहायता के अधिन वित्तबान बने के लिए संविदा की एक प्रति जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और इस के साथ-साथ उपयुक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सैंट लेखा व लेखा परक्षा नियंत्रक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3) जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक का जापान अनुभाग उसका सूचना सहायता लेखा व लेखा परक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. मा. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापाना संभरक को भुगतान करने के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को अनुबंध 2 के अनुसार एक “भुगतान प्राधिकार पत्र” (ए/प) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/प) के प्रतिया भारत का दूतावास टोकियो, आयातक, भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजे जाएंगी।

3(4) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/प) के प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और महायता लेखा एवं लेखा परक्षा नियंत्रक को सूचना देते हुए इस प्राप्ति को सूचना से संभरक को अवगत कराएगा।

3(5) पोतलवान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/प में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा। यदि दस्तावेज सह पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापाना संभरक को अपने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6) जापानी संभरक को भुगतान का व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंक खर्च भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत में आयातक से संबद्ध बैंक द्वारा बैंक आफ इंडिया टोकियो को धन परेषित करने निर्णीत किया जाएगा।

**खण्ड-4 रुपये जमा करने का उत्तरदायित्व**

4(1) मूल विनियम पोतपरिवहन दस्तावेज साथ ही साथ बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबद्ध बैंक को भेजे जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को अनुबंध 1 के (प) में उल्लिखित है, की शाखा होगी। उस बैंक का दस्तावेजों के ये विनियम सैंट केवल इस बात का मुनिस्वय कर लेने के बाद ही संबद्ध आयातक को देने चाहिए कि जापानी संभरक को चुकाई गई धन धनराशि के बराबर रुपये उस मामलों में जहां देने योग्य है व्याज के खर्च सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उस धनराशि पर जापानी संभरक का बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि से वास्तविक

रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से हिसाब लगाकर व्याज सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार सरकारी लेख में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों दिनों, अर्थात् जिनदिन जपानी संभरक को भुगतान किया जाता है, और जिस दिन सरकारी लेख में रूपया जमा किया जाता है, के लिए देय है। देखिए सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 भुगतानों की येन धनराशि के बराबर रूप की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली विनियम दर मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76 दिनांक 17-1-76 में निर्धारित मुद्रा विनियम की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनियम नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए। इस संबंध में कोई भी परिवर्तन जब और जैसे हो आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया जाएगा। इस बात का सुनिश्चय करने का उत्तरदायित्व संबंध भारतीय बैंक का होगा कि आयात दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले देय धनराशि सरकारी लेख में मढ़ी रूप से जमा कर दी गई है। साहस्येधारी को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरो से दस्तावेज लेने से पहले ही देय धनराशि लेख में सही रूप से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चय करने की आगारु को जिम्मेदारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेख में ठीक से जमा करना दी गई है जब कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्वगी प्राप्त की हो, उस मामले में जब आयातक सरकार को देय धनराशि माल छुड़वाने से पूर्व जमा करवाने में असमर्थ होता है तो उसे आगे ए/पी जारी करना रोक दिया जाएगा और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा जिससे ऐसे आयातक को आगे कोई आयात लाइसेंस न जारी किया जाए जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रूपया जमा करना चाहिए वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट फोर परचेजिंग एटमेट्रा एन्ड परचेजिंग अन्डर ग्रान्ट एंड फ्राम वि गवर्नमेंट, आफ जापान" फार 1984-1985 "ग्रान्ट फार परचेज आफ वि एजुकेशनल एंड रिसर्च इन्विपमेंट एंड सर्विसेज नेसेसरी फार इन्स्टालेशन आफ वि इन्विपमेंट/ट्रान्सपोर्टेशन आफ इन्विपमेंट टू पोर्ट्स इन इंडिया बाई वि यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली" होगा।

4 (2) शासन के बाएँ कोने में कोड नं. 5130000009 दर्शाने पर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की साथ में एक जमा होनी चाहिए, या यदि यह सुविधाजनक न हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इसके उपतंगी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक (हुण्डीकर्ता) से प्राप्त एक हुण्डी (हिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (हुण्डी ग्राह्य और ापक) में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आईटीसी (पीएन)/68 दिनांक 30-8-1968 सं. 233-आईटीसी (पीएन)/68, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 5-10-71, सं. 74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित सरकारी लेख में जमा करने के लिए धन परेषण करना चाहिए।

4 (3) सरकार द्वारा एसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर संबंध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजना जो भारत सरकार द्वारा मंगी जाए। शासन के विभिन्न कालों में भारत समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाये वाली सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-71 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना सं.

74-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 31-5-74 में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूरा व्योरे" में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

- (क) वित्त मंत्रालय भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की सं. और दिनांक।
- (ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निरूपित किए जाने हैं।
- (ग) जापानी संभरक को भुगतान करने की तिथि।
- (घ) चुकाए गए व्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है।
- (ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(व्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेख में समुल्य रूपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जाती है)। उसके पश्चात् सी. ए. ए. द्वारा जारी किए गए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र का संबंध देते हुए और बीजक तथा पाँच परिवहन दस्तावेजों की प्रतियों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रूपया जमा करने का माध्यम देने हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाता चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि वष एक निरूप बैंक आफ इंडिया, टोकियो से अवश्य ही की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4 (4) भारत में संबंध बैंक आफ इंडिया, की लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रूपया निरूपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अवेकित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक आफ बम्बई को भेजना चाहिए।

#### खण्ड-5 विविध प्रावधान

##### 5(1) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद आयातक को पोतलदानों और उनके अधीन किए गए भुगतानों के संबंध में और जा पोतलदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी. ए. ए. एण्ड ए. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग संसद् मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

आयातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत माल के आयात से संबंधित किसी ऐसी विशेष शर्त में संभरक का अवगत कराए जो समशीति का पालन करने में संभरको पर प्रभाव डालती हो।

##### 5(2) विवाद

यह समझ लेना चाहिए कि आयातक और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्व संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्त सार्वनाक "भुगतान के नियमों" में अनुबध-1 में आयातक द्वारा दर्शाई जाती चाहिए। विवादों से निरादने की शर्त ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

##### 5(3) भविष्य अनुदान

आयातों या उनके परर में उन्नत विनी मानने या गर्म मामला से संबंधित जापान से 1984-85 के लिए अनुदान सहायता के अधीन

सभी आयातों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों या अनुदेशों या आदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना होगा।

#### 5(4) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपयुक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

#### 5(5) अनुबंधों की सूची

अनुबंध 1—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करने के लिए आवेदन करने का प्रपत्र।

अनुबंध 2—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) का प्रपत्र।

#### अनुबंध- 1

“भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र”

संख्या

दिनांक

सेवा में,

सहायता सेवा तथा सेवा परीक्षा नियंत्रक,  
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,  
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल  
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय:—1984-85 के लिए येन 500 मिलियन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से उपस्कर लगाने/भारत में पत्तों पर उपस्कर के परिचालन के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अनुसंधान उपस्करों और सेवाओं का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपयुक्त उपस्कर के आयात के संबंध में हम आपको निम्नलिखित ब्यौरा भेजते हैं जिसके कि आप सम्बद्ध जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी कर सकें—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की सं., दि. और मूल्य और वह तिथि जब तक यह वैध है।
- (ग) अधिप्राप्ति के तरीके तथा यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित छुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणों सहित यह निविष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ) माल का उद्गम देश।
- (च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।
- (छ) यदि कोई हो तो, भारतीय रुपए में भारतीय एजेंट के कमिशन की धनराशि (येन में)।
- (ज) यह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा का नाम और दिनांक।
- (ञ) जापानी संभरक का नाम और पता।
- (ट) वे भुगतान और संभावित तिथि जिनको संविदाओं के अंतर्गत भुगतान देय होंगे।

(ठ) माल की सुपुर्दगी पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथियाँ।

(ड) बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान वशति हुए)।

(ढ) पोतलवान अनुदेश (अनुमेष या गैर अनुमेष वाहनांतरण/आंशिक पोतलवान) निविष्ट कीजिए।

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता:—“हम एतद्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को देय धनराशि के समतुल्य रुपएकी पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रबलित दर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (अर्थात् सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राष्ट्रों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।”

भवदीय,

अनुबंध- 2

संख्या एक  
वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
नई दिल्ली,

सेवा में,

बैंक आफ इंडिया,  
टोकियो शाखा,  
टोकियो (जापान)

विषय:—1984-85 के लिए येन 500 मिलियन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत में उपस्कर लगाने/भारत में पत्तों के लिए उपस्कर के परिचालन के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अनुसंधान उपस्करों और सेवाओं का आयात-भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ ..... को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा परिशिष्ट में दिए गए यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वो ..... की ..... येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. कृपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों को सूचना दें और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार, आयातक बैंक, भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा संकेतित सवान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. आयातक द्वारा आपको दस्तावेज संभरको एवं बैंकों के प्रसार को भेजने आदि के लिए आड़े सहित अबा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए सवान दस्तावेज आदि के आधार पर आपके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है त



इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को भेजी जानी चाहिए।

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा सकता है।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र..... तक वैध रहेगा।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:—

1. आयातक.....को उनके पत्र सं..... दिनांक.....के संदर्भ में। उनसे अनु रोध किया जाता है कि वे बैंकों से परकाम्य वस्तुओं की सुपुर्गो लेने से पूर्व अपने बैंकों के माध्यम से रुपए निक्षेप आवि को जमा करवाने की व्यवस्था करें। यदि विशेष परिस्थितियों की वजह से मूल परिवहन वस्तावेज प्रस्तुत किए बिना सीमाशुल्क प्राधिकारियों और पत्तन के प्राधिकारियों से माल की सुपुर्गो सीधे ही प्राप्त करली हो, तो वहाँ सुपुर्गो प्राप्त करने से पूर्व धनराशि जमा करवाना चाहिए। विदेशी संभरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते हैं वैसे ही धनराशि जमा करवाना देनी चाहिए। सीमा ही और सही रूप से धनराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग प्रांति में उल्लिखित कार्रवाई की जाएगी।

2. आयातक का बैंक.....उनसे निवेदन किया जाता है कि भारतीय बैंक आफ इंडिया, टोकियो, नांव से वस्तावेज प्राप्त करने पर जापानी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रुपया जमा करने का व्यवस्था करें। संभरकों को बुकायी गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए, के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि से भारतीय बैंक को अवायगी करने की तिथि तक सरकार के लेखों में तुल्य रुपया जमा करने की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं. 31-आई टी सी (पी एन)/83, दिनांक 10-8-83 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 12% वार्षिक दर पर और इसके अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 18% की दर से ध्याज भी सरकारी लेखों में जमा करना होगा। ध्याज दोनों दिनों के लिए देय होगा अर्थात् वह तिथि जिसको विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिस दिन सरकारी लेखों में रुपया निक्षेप किया जाता है। (यदि इस दर में कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी)। इस बात का धुमिश्रय कर लेना चाहिए कि सीमा-शुल्क निकासी के लिए आयातक को वस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा कराई जाती है।

चालान के बाएं कोने में कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए धनराशियां या तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा या इनकी अनुगो संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीय-कृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्ति की गई स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाना) के नाम में और उसकी देय वर्षानी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए। इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 233-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 24-10-68 सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई.

टी. सी. (पी एन)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर विनाया जाता है। लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स एण्ड एडवांस—843 निविल डिपोजिट—डिपोजिट्स फार परचेजिस एटसेकड़ा एक्साड परचेजिस अन्डर ग्राण्ट एंड क्रोम दि गवर्नमेंट आफ जापान फार 1984-85 अन्डर डिटेन्ड हैड 500 मिनिशन ग्रांन्ट एंड फार परचेज आफ एजुकेशनल एंड रिसर्च इक्विपमेंट एंड सर्विसेज मेमेसरी फार इन्स्टीटयूशन आफ दि इन्विमेंट/ट्रांसपोर्टेशन टू पोर्ट इन इंडिया" है।

जिन मामला मे तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिनिधि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए प्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:—

लेखा तथा लेखा परीक्षा निबंधक,  
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),  
पहली मंजिल, यू सी ओ बैंक बिल्डिंग,  
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतिक सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित वर्षानी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचना उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में ध्याज की बुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ध्याज की गणना की गई है और उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा व्योरा इन विभाग की भेजना चाहिए।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खातों सहित यदि कोई हो तो, बैंकिंग खातों और बैंक आफ इंडिया, टोकियो नांव के अन्य खातों इंडियन बैंक और बैंक आफ इंडिया टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो।

5. अवर सचिव (टी सी) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

(लेखा अधिकारी)

## MINISTRY OF COMMERCE IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 79-ITC(PN)/84-85

New Delhi, the 9th January, 1985

Subject : Licensing conditions for purchase of Educational and Research equipments and services necessary for installation of the equipment/transportation of equipment to ports in India under Japanese grant aid of Yen 500 Million for 1984-85 to University of Delhi.

File No. IPC/23(8)/84.—The terms and conditions governing imports under the Japanese Grant Aid of Yen 500 Million for 1984-85 by the University of Delhi as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN.  
Chief Controller of Imports and Exports.

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE,  
PUBLIC NOTICE NO. 79-ITC(PN)84-85  
DATED 9-1-1985

Licensing Conditions for purchase of Educational and Research equipment and services necessary for installation of the equipment|transportation of the equipment to ports in India under Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen five hundred million (Yen 500,000,000).

Section I—General conditions :—

I (i) The Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 500 million (C&I) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for purchase of educational and research equipment and services necessary for the installation of the equipment|transportation thereof to ports in India, by the University of Delhi.

I (ii) The import licence should be issued for an amount not exceeding Yen 550 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 500 million Japanese Grant Aid for 1984-85". The licence code for the first and second suffix will be "SJN".

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (iv) The equipment and services should be procured only from Japan|India under this Grant Aid. The purchase order should be placed only on the Japanese suppliers.

I (v) The import licence will be issued on CIF basis with validity upto 31-3-1985.

I (vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1985"

I (vii) The contract value (C&F|FOB basis) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency.

The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I (viii) The purchase contract should be entered into only in Japanese Yen with the Japanese nationals or Japanese juridical persons controlled by Japanese nationals.

Section II—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 12th October, 1984 between the Government of India and Government of Japan concerning the Grant Aid of Yen 500 million for 1984-85 and will be subject to the approval of both the Governments.

II (ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorization to Pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1984-85.

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the Shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III. Contract Approval by Governments of India and Japan :—

III (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (TC), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi, 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send one copy of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1984-85 of Yen 500 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid

Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and the CAA&A.

III (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese Supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittance to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

#### Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV (i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18% for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposits are made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers. The importer should

also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further A/P to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import licence is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-deposits and Advances-843-Civil Deposits-Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grants Aid from the Government of Japan - for 1984-85"-Grant for purchase of the educational and research equipment and services necessary for the installation of the equipment/transportation of equipment to ports in India by the University of Delhi.

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1975 is invariably indicated in the column "full particulars of remittance and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans :

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and date.
- (b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the Japanese supplier.
- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.



## (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account)

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA & A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV. (iv) The concerned Bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

## Section V. Miscellaneous provisions

## V. (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

## V. (ii) Disputes

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

## V. (iii) Future Instructions

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1984-85 from Japan.

## V. (iv) Breach or violation.

Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

## V. (v) List of Annexures :

Annexure—I :—Request for issue of A/P.

Annexure—II :—Form of A/P.

## ANNEXURE-I

## "REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORIZATION TO PAY"

To

No.

The Controller of Aid Accounts & Audit,  
Ministry of Finance,  
Department of Economic Affairs,  
UCO Bank Building, 1st Floor,  
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Import of educational & research equipment and services necessary for the installation of the equipment/transportation of the equipment to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 500 million for 1984-85

Sir,

In connection with the import of above mentioned equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned :—

- (a) Name and address of Indian Importer.
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.
- (c) Method of procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C & F or FOB value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F or FOB value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Name & date of the contract with Japanese Suppliers.
- (j) Name & address of the Japanese Supplier.
- (k) Payment terms & probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/partshipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of Importer's bank in India.
- (p) Undertaking by the importer :—"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment